आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए किसी दस्तावेज की जरुरत नहीं

नई दिल्ली (ईएमएस)। आज के दौर में १२ अंकों की पहचान संख्या यानी आधार नंबर हर भारतीय के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आधार कार्ड से ना सिर्फ हमारे पते की पुष्टि होती है, बल्कि आपकी पहचान का सत्यापन भी होता है। हालांकि, साथ ही साथ कई तरह की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपके आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर अपेडेट हो। इसका सीधा मतलब यह है कि आप जो मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं,वहीं नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। हालांकि, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ अपडेटेड नहीं है,तब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल में ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। यूआईडीएआई ने ट्वीट कर कहा है कि आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर को ऐड करने के लिए किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। आपको बस अपना आधार कार्ड लेकर निकटतम आधार सेवा केंद्र जाना होगा। आधार सेवा केंद्र पर आप मोबाइल नंबर को ऐड या अपडेट करने का रिक्वेस्ट कर पाएंगे।

आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का अपडेटेड होना काफी जरूरी होता है। इससे आपको आधार से जुड़ी विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है। मसलन, मोबाइल नंबर अपडेटेड होने पर आप घर बैठे आधार कार्ड में नाम, पता से विवरण अपडेटेड करा सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफ से जुड़ी कई तरह की सेवाओं का लाभ भी आप घर बैठे उठा सकते हैं।

निर्मला ने ब्रीफकेस वाली परंपरा को तोड़ा, लाल रंग के मखमली कवर वाली फाइल में लेकर पहुंची संसद

नई दिल्ली (ईएमएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण १ फरवरी को वित्त वर्ष २०२१-२२ में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगी। २०१९ में लोकसभा चुनाव होने के कारण फरवरी २०१९ में अंतरिम बजट पेश हुआ और फिर जुलाई २०१९ में फुल आम बजट आया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पांच बार तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सीतारमण पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री बनीं थी। मोदी सरकार-२ में वह देश की पहली महिला वित्तमंत्री बनीं।

२०१९ में वित्त मंत्री निर्मला ने बजट को लेकर अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही एक परंपरा को तोड़ दिया। दरअसल, वित्त मंत्री जब भी बजट पेश करने आते हैं,तब ब्रीफकेस लेकर आते हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस वाली परंपरा को तोड़ दिया। वह लाल रंग की मखमली कवर वाली फाइल में बजट लेकर संसद पहुंचीं थीं। लाल रंग का मखमली कवर वाला बजट कैमरों के सामने आते ही चर्चा का विषय बना गया।

इस कदम से पारंपरिक बजट ब्रीफकेस की जगह बहीखाते के इस्तेमाल को अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई पश्चिमी दासता को खत्म करने के तौर पर भी देखा गया। मालूम हो कि बजट शब्द फ्रेंच शब्द बोगेट से आया है, जिसका मतलब ब्रीफकेस होता है। जबकि, बहीखाते को अंग्रेजी में अर्थ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहते हैं। बहीखाते के ऊपर लगा अशोक स्तंभ इस बात का इशारा करता है कि अब बजट से पश्चिमी सोच को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। बजट में सरकार अपने अकाउंट को ही जनता के सामने रखती है। वार्षिक बजट में उन स्रोतों के बारे में जानकारी होती है जिनसे सरकार के पास पैसे आते हैं। इसके अलावा बजट में विभिन्न मदों की डिटेल होती है, जिसके तहत सरकार खर्च करती है।

क्या है ब्रीफकेस का इतिहास

आजादी के बाद पहले वित्त मंत्री आरके शंकमुखम चेट्टी बजट पेश करने के लिए ब्रीफकेस लेकर संसद पहुंचे थे। १९५८ में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर यह परंपरा आगे बढ़ती गई। हालांकि, कृष्णामचारी और मोरारजी देसाई बजट ब्रीफकेस लेकर संसद नहीं पहुंचे, बल्कि वे अपने साथ फाइल लेकर आए थे।

कोरोना संकट काल में भी अरबपतियों की मौज, दौलत ३५ प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली (ईएमएस)। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की दौलत ३५ प्रतिशत बढ़ गई, जबकि इस दौरान करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया था। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च २०२० के बाद की अवधि में भारत में १०० अरबपतियों की संपत्ति में १२,९७,८२२ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इतनी राशि का वितरण यदि देश के १३.८ करोड़ सबसे गरीब लोगों में किया जाए,तब प्रत्येक को ९४,०४५ रुपये दे सकते हैं। रिपोर्ट में आय की असमानता का जिक्र करते हुए बताया गया कि महामारी के दौरान मुकेश अंबानी को एक घंटे में जितनी आमदनी हुई, उतनी कमाई करने में एक अकुशल मजदूर को दस हजार साल लग जाएंगे, या मुकेश अंबानी ने जितनी आय एक सेकेंड में हासिल की, उसे पाने में एक अकुशल मजदूर को तीन साल लग सकते है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी पिछले सौ वर्षों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है और इसके चलते १९३० की महामंदी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ।

ऑक्सफैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर ने कहा, रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से कैसे सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौरान सबसे धनी लोगों ने बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की, जबकि करोड़ों लोग बेहद मुश्किल से गुजर-बसर कर रहे हैं। रिपोर्ट के लिए ऑक्सफैम द्वारा किए गए सर्वेक्षण में ७९ देशों के २९५ अर्थशास्त्रियों ने अपनी राय दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी, गौतम अडाणी, शिव नादर, सायरस पूनावाला, उदय कोटक, अजीम प्रेमजी, सुनील मित्तल, राधाकृष्ण दमानी, कुमार मंगलम बिरला और लक्ष्मी मित्तल जैसे अरबपतियों की संपत्ति मार्च २०२० के बाद महामारी और लॉकडाउन के दौरान तेजी से बढ़ी। दूसरी ओर अप्रैल २०२० में प्रति घंटे १.७ लाख लोग बेरोजगार हो रहे थे।

रिपोर्ट के भारत केंद्रित खंड में बताया गया, भारतीय अरबपतियों की संपत्ति लॉकडाउन के दौरान ३५ प्रतिशत बढ़ गई। भारत अरबपतियों की संपत्ति के मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद छठे स्थान पर पहुंच गया। भारत के ११ प्रमुख अरबपतियों की आय में महामारी के दौरान जितनी बढ़ोतरी हुई, उससे मनरेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय का मौजूदा बजट एक दशक तक प्राप्त हो सकता है।' ऑक्सफैम ने कहा कि महामारी और लॉकडाउन का अनौपचारिक मजदूरों पर सबसे बुरा असर हुआ। इस दौरान करीब १२.२ करोड़ लोगों ने रोजगार खोए, जिनमें से ९.२ करोड़ (७५ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्र के थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इस संकट के चलते महिलाओं ने सबसे अधिक कष्ट सहा और '१.७ करोड़ महिलाओं का रोजगार अप्रैल २०२० में छिन गया। महिलाओं में बेरोजगारी दर लॉकडाउन से पहले ही १५ प्रतिशत थी, इसमें १८ प्रतिशत की और बढ़ोतरी हो गई।' इसके अलावा स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी होने की आशंका भी जताई गई।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया, भारत की अर्थव्यवस्था २०२१ में ७.३ प्रतिशत की दर से बढ़ेगी

संयुक्त राष्ट्र (ईएमएस)। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था २०२१ में ७.३ प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, जबकि कोरोना और लॉकडाउन के चलते २०२० में इसमें ९.६ प्रतिशत संकुचन होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डीईएसए) द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था २०२० में कोविड-१९ के चलते शताब्दी के सबसे बड़े संकट से प्रभावित हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि २०२१ में ७.३ प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष २०२१ में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा। इस दौरान चीन की वृद्धि दर ७.२ प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष २०२० में ९.६ प्रतिशत की दर से घटेगी। इस दौरान कोरोना को काबू में करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से घरेलू खपत में कमी आई है। पिछले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में ४.३ प्रतिशत की कमी हुई, जो २००९ के संकट के मुकाबले ढाई गुना से अधिक गिरावट है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि २०२१ में ४.७ प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो २०२० के नुकसान को कुछ कम करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-१९ महामारी के विनाशकारी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को आने वाले वर्षों में महसूस किया जाएगा।

डिजिटल क्षेत्र में दिलचस्पी के चलते भारत में २०२० में एफडीआई १३ प्रतिशत बढ़ा : संयुक्त राष्ट्

न्यूयॉर्क (ईएमएस)। वैश्विक निगरानी संस्था संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि डिजिटल क्षेत्र में दिलचस्पी के चलते भारत में २०२० में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) १३ प्रतिशत बढ़ा, हालांकि इस दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी का प्रवाह बहुत तेजी से घटा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कोविड-१९ महामारी के बीच भारत और चीन ने विदेशी पूंजी को आकर्षित किया। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) द्वारा रविवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक २०२० में वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के ४२ प्रतिशत घटकर ८५९ अरब अमेरिकी डॉलर रह जाने का अनुमान है, जो २०१९ में १५०० अरब डॉलर था। पिछली बार इतना निचला स्तर १९९० के दशक में देखा गया था और यह गिरावट २००८-२००९ के वैश्विक वित्तीय संकट के मुकाबले ३० प्रतिशत अधिक है। अंकटाड ने कहा कि एफडीआई में गिरावट खासतौर से विकसित देशों में देखने को मिली, जहां एक अनुमान के मुताबिक पूंजी प्रवाह ६९ प्रतिशत घटकर २२९ अरब डॉलर रह गया। हालांकि दूसरी ओर डिजिटल क्षेत्र में निवेश से भारत में एफडीआई १३ प्रतिशत बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक एफडीआई चीन में आया और यहां पूंजी प्रवाह चार प्रतिशत बढ़कर १६३ अरब डॉलर हो गया।

सोमवार को बदली चाल, मार्केट कैंप के लिहाज से आरआईएल को पछाड़, टीसीएस शीर्ष पर

मुंबई (ईएमएस)। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को झटका लगा है। टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) अब आरआईएल को पछाड़कर सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। टीसीएस का मार्केट कैप १६९.९ अरब डॉलर (करीब १२,४३,५४०.२९ करोड़ रुपए) को पार कर गया है। सोमवार की सुबह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत कम होकर १,९५७ रुपए तक चली गई थी। वहीं टीसीएस के शेयर की कीमत ३,३१८ रुपए है। सुबह ११:५३ बजे बीएसई में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ४.५२ प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं टीसीएस का शेयर ०.५३ प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा है। पिछले साल अक्टूबर में भी एक ऐसा मौका रहा, जब भारत की दिग्गज आईटी कंपनी ने एक्सेंचजर को सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली सॉफ्टवेयर कंपनी के मामले में पीछे छोड़ा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारत में १२ लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप का प्रतिमान बनाने वाली कंपनी का रिकॉर्ड भी टीसीएस के नाम है। साल २०१८ में आईबीएस इस मार्केट में शीर्ष कंपनी थी। उस दौरान आईबीएस का कुल रेवेन्यू टीसीएस की तुलना में करीब ३०० फीसदी ज्यादा था। इसके बाद दूसरे स्थान पर एक्सचेंजर का नाम था। हालांकि, पिछले साल ही अप्रैल में टीसीएस का मार्केट १०० अरब डॉलर के पार पहुंचा था। ०८ जनवरी २०२१ को टीसीएस ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए थे। तीसरी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था। उसके बाद से ही इस शेयर में तेजी बनी हुई है। ३१ दिसबंर २०२० को समाप्त इस तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा ८,७०१ करोड़ रुपए रहा है जिसके ८५१५ करोड़ रहने का अनुमान था। पिछली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा ८,४३३ करोड़ रुपए रहा था। तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में तिमाही आधार पर १६.४ फीसदी और सालाना आधार पर ७.१ फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी तरह तीसरी तिमाही में कंपनी की आय में तिमाही आधार पर ४.७ फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जबकि सालाना आधार पर कंपनी की आय में ५.५ फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। तीसरी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेट आय ४२,०१५ करोड़ रुपए रही है जबकि इसके ४१,३५० करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। सितंबर तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय ४०,१३५ करोड़ रुपए रही थी।

लॉकडाउन में ३५ प्रतिशत बढ़ी अरबपतियों की संपत्ति: ऑक्सफैम

नई ?दिल्ली (ईएमएस)। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में ३५ प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई, जबकि इस दौरान करोड़ों लोगों को खाने का संकट पैदा हो गया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इनइक्वालिटी वायरस में कहा गया ?कि मार्च २०२० के बाद की अवधि में भारत में १०० अरबपतियों की संपत्ति में १२,९७,८२२ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इतनी राशि का वितरण यदि देश के १३.८ करोड़ सबसे गरीब लोगों में किया जाए, तो इनमें से प्रत्येक को ९४,०४५ रुपए दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट में आय की असमता का जिक्र करते हुए बताया गया कि महामारी के दौरान मुकेश अंबानी को एक घंटे में जितनी आमदनी हुई, उतनी कमाई करने में एक अकुशल मजदूर को दस हजार साल लग जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी पिछले सौ वर्षों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है और इसके चलते १९३० की महामंदी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ। ऑक्सफैम के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा ?कि इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से कैसे सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौरान सबसे धनी लोगों ने बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की, जबकि करोड़ों लोग बेहद मुश्किल से गुजर-बसर कर रहे हैं।

कोविड-१९ के मरीजों पर उसकी दवा के परीक्षण के नतीजे सकारात्मक: जायडस कैडिला

नई दिल्ली (ईएमएस)। दवा कंपनी जायडस कैडिला ने कहा कि मैक्सिको में कोविड-१९ के मरीजों पर उसकी दवा डेसीडुस्टैट के दूसरे चरण के परीक्षण के नतीजे सकारात्मक हैं। जायडस कैडिला को जून २०२० में मैक्सिको के नियामक प्राधिकरण से कोविड-१९ के इलाज की संभावित दवा डेसीडुस्टैट के परीक्षण की अनुमति मिली थी। कैडिला हेल्थकेयर ने बताया कि कोविड के इलाज में डेसीडुस्टैट के दूसरे चरण के परीक्षण सकारात्मक रहे हैं। कंपनी ने बताया कि दवा के इस्तेमाल से लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में बढ़ोतरी हुई और ऑक्सीजन स्तर में भी सुधार हुआ।

मोंटेक ने कहा- धीरे-धीरे उबर रही है देश की अर्थव्यवस्था

पुणे (ईएमएस)। पूर्ववर्ती योजना आयोग के पूर्व डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ने धीरे-धीरे उबरना शुरू कर दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत होने के पहले से ही नरमी आने लगी थी। महामारी के चलते लॉकडाउन लगाये जाने के बाद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घरेलू अर्थव्यवस्था में २३.९ प्रतिशत की भारी-भरकम गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि इसके बाद दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था ने तेज वापसी की और गिरावट की दर कम होकर ७.५ प्रतिशत रह गई। अहलूवालिया ने कहा ?कि महामारी के चलते लॉकडाउन जरूरी हो गया था और उसके चलते हम पहली तिमाही में चोटी से फिसल गए। अब अर्भव्यवस्था वापस चढ़ रही है। मुझे लगता है कि यह क्रमिक सुधार है, लेकिन स्पष्ट है कि सुधार हो रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसा देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में चालू वित्त वर्ष २०२०-२१ के दौरान रिकॉर्ड ७.७ प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। अहलूवालिया ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र ठीक हो रहा है और २०१९-२० की स्थिति में वापस आ गया है। हालांकि होटल, रेस्तरां, यात्रा, पर्यटन और मॉल में खुदरा खरीदारी जैसे क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हैं। इन्हें सामान्य स्थिति में लौटने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा कि देश में बुनियादी ढांचा अभी भी पीछे है और अगली कुछ तिमाहियों में इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। अहलूवालिया ने लघु उद्योगों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिये सरकार और रिजर्व बैंक की सराहना की।

दिसंबर तिमाही में १.८४ अरब डॉलर के १९ आईपीओ आए: रिपोर्ट

नई ?दिल्ली (ईएमएस)। बीते वर्ष दिसंबर, २०२० में समाप्त चौथी तिमाही में १.८४ अरब डॉलर के १९ आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) आए, जो भारतीय बाजार के मजबूती के रुख को दर्शाता है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार की धारणा सकारात्मक बनी हुई है, जिससे आईपीओ बाजार के लिए २०२१ का साल भी अच्छा रहने की उम्मीद है। प्रमुख परामर्शक ईवाई इंडिया की आईपीओ के रुख पर २०२० की चौथी तिमाही की रिपोर्ट में कहा गया है कि तिमाही के दौरान १० आईपीओ मुख्य बाजार में नौ लघु एवं मझोले उपक्रम (एसएमई) खंड में आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ताजा दिसंबर तिमाही में १.८३६ अरब डॉलर के १९ आईपीओ आए। सबसे बड़ा आईपीओ ग्लैंड फार्मा का ८६.९ करोड़ डॉलर था। इससे पिछले साल समान अवधि में ११ आईपीओ आए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर २०२० में आईपीओ की संख्या के मामले में भारत नौवें स्थान पर रहा। २०२० में देश में ४३ कंपनियों ने आईपीओ से कुल ४.०९ अरब डॉलर जुटाए।

जयंति घोष यूएन की आर्थिक, सामाजिक मामलों की उच्चस्तरीय समिति में शामिल

न्यूयॉर्क (ईएमएस)। वैश्विक निगरानी की शीर्ष संस्था संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारत की विकास अर्थशास्त्री जयंति घोष को एक उच्चस्तरीय सलाहकार समिति में शामिल किया है, जो कोविड-१९ के बाद पैदा होने वाली प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर प्रतिक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सुझाव देगी। इस समिति में कुल २० सदस्य हैं। घोष (६५) यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। उन्होंने लगभग ३५ वर्षों तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अर्थशास्त्र पढ़ाया है और कई किताबें लिखी हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (यूएनडीईएसए) ने बताया कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपने बौद्धिक नेतृत्व के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध २० प्रमुख हस्तियों को मिलाकर आर्थिक और सामाजिक मामलों पर दूसरे उच्च-स्तरीय सलाहकार बोर्ड (एचएलएबी) का गठन किया जाएगा। बोर्ड अलगे दो वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक और स्थानीय स्तर पर नीति निर्माण के लिए सलाह देगा।

बदहाल आर्थिक स्थिति के बीच सीरिया ने पेश किया नया बैंक नोट

दमिश्क (ईएमएस)। बदहाल होती आर्थिक स्थिति के बीच सीरिया ने पांच हजार सीरियाई लीरा का बैंक नोट पेश किया। यह अब सीरिया में चलन में सबसे बड़ा नोट हो गया है। सीरिया करीब एक दशक से घरेलू संघर्ष से जूझ रहा है। साल २०११ में घरेलू संकट शुरू होने के बाद से ही सीरियाई मुद्रा लीरा लगातार कमजोर हो रही है। १० साल पहले २०११ में लीरा की दर ४७ प्रति डॉलर थी, जो अब आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कमजोर होकर १,२५० प्रति डॉलर पर आ चुकी है। हालांकि खुले बाजार में लीरा की दर करीब २,५०० प्रति डॉलर तक है। मुद्रा के इस तरह से कमजोर होने के चलते सीरिया में खाद्य सामग्रियों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। सीरिया के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार औसत मुद्रास्फीति की दर २०१९ की तुलना में २०२० में २०० प्रतिशत पर पहुंच गई। माल की मुद्रास्फीति ३०० प्रतिशत तक पहुंच गई। प्रमुख खाद्य पदार्थों, जैसे दाल और वनस्पति तेल की कीमतों में लगभग १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महामारी से जुड़ी पाबंदियों ने सीरिया की आर्थिक कठिनाइयां और बढ़ा दी हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक आकलन के अनुसार करीब ८० प्रतिशत सीरियाई लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं। इस बीच सीरिया के केंद्रीय बैंक ने नए नोट के बारे में कहा कि बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे जारी किया गया है। इस नए बैंक नोट में एक तरफ सीरिया के झंडे को सलामी देते सैनिक की तस्वीर है।

टेस्ला ने इंजीनियर पर किया मुकदमा, चुराई थीं सीक्रेट फाइल

नई दिल्ली (ईएमएस)। दुनिया के प्रमुख कारोबारी एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला ने कहा है ?कि उनके पूर्व कर्मचारी ने २६ हजार फाइलों की चोरी की है१ यह कर्मचारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और कंपनी छोड़ने से पहले उसने कंपनी का सीक्रेट चुरा लिया है। इन फाइलों के डाटा को चुराकर उसने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है१ कंपनी ने बताया कि इस इंजीनियर का नाम एलेक्स खातिलोव है। वह दो हफ्तों से कंपनी के साथ काम कर रहा था। कंपनी की ओर से की गई शिकायत में कहा गया है कि खातिलोव ने कंपनी की स्क्रिप्ट्स को चोरी किया गया है जो कि कई तरह के कारोबार से जुड़ी हुई थीं। गौरतलब है ?कि टेस्ला ने यूएस डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपनी दलील में कहा कि इस चोरी से कंपनी के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस पर जज ने खातिलोव को तुरंत सभी फाइल्स, रेकॉर्ड्स और ईमेल कंपनी को लौटाने और ४ फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। टेस्ला ने दूसरे पूर्व कर्मचारियों और प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। टेस्ला ने उन पर उसके इंजीनियरों को अपनी तरफ खींचने और प्रोप्राइटरी डेटा चोरी करने का आरोप लगाया है।

बीपीसीएल नई मुहिम से १० गुना कर सकती है उपभोक्ता आधार

मुंबई (ईएमएस)। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को एक नयी मुहिम से अपने ग्राहक आधार को १० गुना बढ़ाकर दस लाख करने की उम्मीद की है। कंपनी ने कहा कि उसने स्मार्टड्राइव कार्यक्रम के तहत १०० गुना बोनस पेट्रोमाइल्स पाय नामक नई मुहिम शुरू की है। इसके तहत उपभोक्ताओं को स्मार्टड्राइव ऐप में मौजूद स्क्रैच कार्ड से ईंधन की हर खरीद पर अतिरिक्त बोनस रिवार्ड प्वायंट जैसे लाभ मिलेंगे। अभी सरकारी कंपनी बीपीसीएल के एक लाख उपभोक्ता हैं। कंपनी अभी स्मार्टड्राइव कार्यक्रम के तहत हर महीने २० करोड़ रुपए से अधिक का लेन-देन करती है।

वाट्सएप का भारतीय व यूरोपीय उपयोगकर्ताओं से अलग-अलग व्यवहार चिंताजनक: केंद्र

नई ?दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वाट्सएप द्वारा निजता नीति को लेकर भारतीय व यूरोपीय उपयोगकर्ताओं से अलग-अलग व्यवहार उसके लिए चिंता का विषय है और वह इस मामले को देख रही है। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा कि यह भी चिंता की बात है कि सोशल नेटवर्किंग मंच वाट्सएप पर भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एकतरफा तरीके से निजता नीति में बदलाव किया जा रहा है। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने सरकार की इस राय से न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की अदालत को अवगत कराया जो फेसबुक के स्वामित्व वाले वाट्सएप द्वारा लाई गई निजता नीति के खिलाफ एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान शर्मा ने अदालत से कहा कि भारतीय उपयोगकर्ताओं को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ डाटा साझा करने के संबंध में विकल्प नहीं देना, प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि वाट्सएप उपयोगकर्ताओं के साथ स्वीकार करो या सेवा नहीं देंगे की नीति पर चल रहा है। उन्होंने कहा ?कि वाट्सएप द्वारा उपयोकर्ताओं को समझौते के लिए मजबूर करने का सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है जिससे सूचना की निजता एवं सूचना सुरक्षा का हित प्रभावित हो सकते हैं।